the pioneer
LUCKNOW SATURDAY | NOVEMBER 3, 2012

# Trg course on post-harvest mgmt of cane inaugurated

PIONEER NEWS SERVICE ■ LUCKNOW

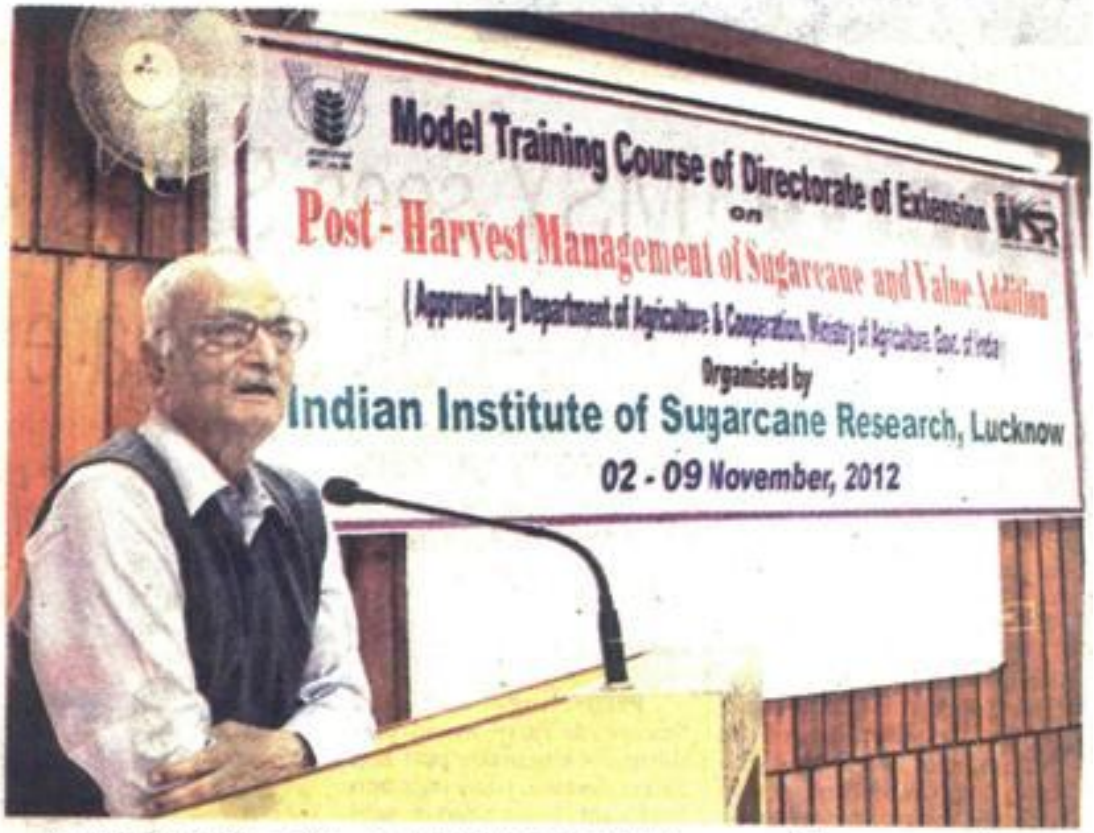


Every year a revenue loss ranging from ₹ 3000-5000 crore is incurred at the national level due to post-harvest losses in sugarcane from its harvesting in the field to its crushing in the sugar mills, said Dr GB Singh, former DG, UPCAR, Government of UP, and former DDG, ICAR, New Delhi.

A model training course sponsored by the Ministry for Agriculture and Cooperation, Government of India, New Delhi, on the "Post-harvest management of sugarcane and value addition" was inaugurated by Dr GB Singh at the IISR here on Friday.

Dr Singh said that the harvesting and crushing schedule of sugarcane should be fine-tuned to reduce this loss to the minimum. Dr Singh stressed the need for increasing sucrose content in sugarcane stalks as the prime researchable area in the near future.

He appreciated the efforts of the IISR in developing a post-harvest management module to reduce the sugar recovery loss to a great extent in sub-tropical India.

In his keynote lecture on post-harvest technology and management, Dr S Solomon, Director, IISR, highlighted the technological options for reducing the post-harvest losses in sugarcane in sub-tropical India.

Dr Solomon said that due to poorly-managed post-harvest activities the country incurred post-harvest losses worth ₹ 50,000 crore in food-grain crops and ₹16,000 crore in sugarcane every year.

As per an estimate, a transit loss of 1.0-1.5 units in sugar recovery during the harvesting of cane in the field to its crushing in the mills occurs, especially in north India, which reduces the production of sugar by 6 to 9 lakh tonnes in Uttar Pradesh alone.

He said that in order to increase sugar production in UP the most viable solution was to check post-harvest losses in sugarcane at least by 50 per cent which may lead to an increase in recovery ranging from 0.5 to 0.75 units.

He said that it was more practical to enhance sugar production in UP keeping in mind the fact that the area under sugarcane would stagnate at 20-25 lakh hectares in the coming years and the cane yield stagnation would be around 60 tonnes per hectare.

In this context the IISR is ready to extend all possible technological support to the sugar industry of UP for curtailing the post-harvest losses.

Dr AK Sah, Senior Scientist, said that the technological options available with the IISR such as chemical spray in standing and cut cane, agronomic and management practices to enhance sucrose content in cane stalk, reducing invertase sugar in matured cane etc could be adopted by the sugar industry to earn additional revenue worth Rs 900-1800 crore every year through 3-6 lakh tonnes of extra sugar.

The course coordinator of the model training course and head, Plant Physiology, Dr A Chandra, said that the technology developed by IISR for value- added products like organic jaggery, granular jaggery, candy, chocolates, sugar syrup, etc would provide enough opportunities to farmers, entrepreneurs and industry to earn extra income in case of surplus sugarcane.

In this eight-day-long model training course 30 sugarcane experts from different states of the country like Punjab, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Bihar and Orissa are participating to learn about the recent advances in post-harvest technologies in sugarcane.

दैनिक प्रभात
लखनऊ, शनिवार ,03 नवम्बर, 2012



# पोस्ट-हारवेस्ट प्रबंधन से बढ़ सकता है चीनी उत्पादन

## गलत प्रबन्धन से बर्बाद हो रहा 16 हजार करोड़ का गन्ना

लखनऊ, प्रभात। गन्ना कटाई से लेकर चीनी मिलों में पेराई के बीच होने वाले पोस्ट-हारवेस्ट हानि के कारण हर वर्ष लगभग 3 हजार से 5 हजार करोड़ रूपये का राजस्व घाटा देश को उठाना पड़ रहा है। यह बात डा जी बी सिंह, भूतपूर्व महानिदेशक कृषि अनुसंधान परिषद ने कही। डा. सिंह भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के सभागार में गन्ना में पोस्ट हारवेस्ट प्रबंधन विषय पर आदर्श प्रशिक्षण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। उन्होनें कहा कि इस राजस्व नुकसान को कम करने के लिए चीनी उद्योग को एक आदर्श कटाई व पेराई समय सारिणी बनाकर दृढ़ता के साथ काम करना होगा।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित की गया है। डा सिंह ने अपने कहा कि गन्ना में सुक्रोज की मात्रा को और अधिक



बढ़ाने के लिए आवश्यक शोध रणनिति पर विचार विमर्श होना चाहिये तथा वैज्ञानिकों को इस दिशा में कार्य करने चाहिये। डॉ. सिंह ने भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित पोस्ट हारवेस्ट मैनेजमैन्ट मॉड्यूल की तारीफकरते हुए कहा कि इस तकनीकी को अपनाकर उत्तर भारत में चीनी परता हअस को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक डा सुशील सोलोमन ने उत्तर भारत में गन्ना व चीनी उत्पादन में पोस्ट हारवेस्ट हानि को कम करने के लिए संस्थान द्वारा विकसित तकनीकों पर प्रकाश डाला।

डा. सोलोमन ने कहा कि खराब पोस्ट हारवेस्ट प्रबंधन के कारण देश में सलाना लगभग 50,000 करोड़ रूपये का खाद्य अनाज एवं 16000 करोड़ रूपये का गन्ना बर्बाद हो जाता है। डा सोलोमन ने यह भी कहा कि उत्तर भारत में गन्ना कटाई से लेकर मिलों में पेराई के अंतराल में होने वाले नुकसान से लगभग 1-0 से 1-5 ईकाई चीनी परता कम प्राप्त होता है जिससे सिर्फ उत्तर प्रदेश में 6 से 9 लाख टन कम चीनी का उत्पादन होता है। प्रदेश में अधिक चीनी उत्पादन करने के लिए गन्ना क्षेत्रफल का बढ़ना मुश्किल है। डा अमरेश चन्द्रा, विभागाध्यक्ष एवं प्रशिक्षण समन्वयक के अनुसार अधिक गन्ना उत्पादन की स्थिति में संस्थान द्वारा विकसित गन्ना से अन्य मूल्यवान उत्पाद बनाने वाली तकनीक जैसे कार्बनिक गुड़, गुड़ पाउडर, शुगर सिरप, गुड़ कैंडी व चॉकलेट, इत्यादि को अपनाकर किसान, उधमी एवं चीनी व गुड़ उद्योग अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। इस आठ दिवसीय आदर्श प्रशिक्षण कार्यक्रम में देश के पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, बिहार एवं उड़ीसा राज्यों से 30 गन्ना विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं।

www.samaylive.com

राष्ट्रीय सहारा

सच कहने की हिम्मत

राष्ट्रीयता • कर्त्तव्य • समर्पण

...दून • वाराणसी से प्रकाशित

लखनऊ । शनिवार • 3 नवम्बर • 2012

# पोस्ट हार्वेस्ट प्रबन्धन से बढ़ सकता है चीनी उत्पादन

लखनऊ (एसएनबी)। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के निदेशक डा. सुशील सोलोमन ने कहा है कि खराब पोस्ट हार्वेस्ट प्रबन्धन के कारण देश में सालाना लगभग 50 हजार करोड़ रुपये का खाद्य अनाज व 16 हजार करोड़ रुपये का गन्ना बर्बाद हो रहा है। इस नुकसान को रोककर चीनी उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। डा. सोलोमन शुक्रवार को संस्थान के सभागार में 'गन्ना में पोस्ट हार्वेस्ट प्रबन्धन' विषय पर आयोजित आदर्श प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुभारम्भ के अवसर पर बोल रहे थे। डा. सोलोमन ने कहा कि उत्तर भारत में गन्ना कटाई से लेकर मिलों में पेराई के अन्तराल में होने वाले नुकसान से सिर्फ उत्तर प्रदेश में छह से नौ लाख टन कम चीनी उत्पादन होता है। प्रदेश में अधिक चीनी उत्पादन करने के लिए गन्ना का क्षेत्रफल बढ़ाना संभव नहीं है। प्रशिक्षण में उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक डा. जीबी सिंह ने कहा कि खेतों में गन्ना कटाई से लेकर चीनी मिलों में पेराई के मध्य होने वाले नुकसान के कारण प्रतिवर्ष लगभग तीन हजार से पांच हजार करोड़ रुपये का राजस्व घाटा देश को उठाना पड़ रहा है। इस नुकसान को कम करने के लिए चीनी उद्योग को एक आदर्श कटाई व पेराई समय सारिणी बनाकर दृढ़ता से काम करना होगा। गन्ना में सुक्रोज की मात्रा को और अधिक बढ़ाने के लिए आवश्यक शोध रणनीति पर विचार-विमर्श होने चाहिए तथा वैज्ञानिकों को इस दिशा में कार्य करने चाहिए। इस अवसर पर संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. एके साह ने कहा कि संस्थान ने आवश्यक पोस्ट हार्वेस्ट तकनीक विकसित की है। इसके तहत खड़े व कटे हुए गन्ने में रसायन का प्रयोग, संस्तुत सस्य क्रियाओं एवं प्रबन्धन तकनीकों को अपनाकर गन्ना में सुक्रोज की मात्रा को बढ़ाना, परिपक्व गन्ने में इनवरटेज सुगर को कम करता आदि को अपनाकर प्रदेश में चीनी उद्योग सालाना तीन से छह लाख टन अधिक चीनी का उत्पादन कर सकता है। विभागाध्यक्ष एवं प्रशिक्षण समन्वयक डा. अमरेश चन्द्रा ने कहा कि अधिक गन्ना उत्पादन की स्थिति में संस्थान की ओर से विकसित गन्ना से अधिक मूल्यवान उत्पाद बनाने वाली तकनीक जैसे कार्बनिक गुड़, गुड़ पाउडर, शुगर सिरप, गुड़ कैंडी व चॉकलेट आदि बनाकर किसान, उद्यमी एवं चीनी व गुड़ उद्योग अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। इस आठ दिवसीय प्रशिक्षण में देश के पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार एवं उड़ीसा राज्य के 30 गन्ना विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं।

**▶ भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में प्रशिक्षण शुरू**

लखनऊ
कैनविज टाइम्स
शनिवार, 03 नवम्बर , 2012

# चीनी उत्पादन में समय सारणी का महत्व

कैनजिव टाइम्स ब्यूरो

लखनऊ। खेतों में गन्ना कटाई से लेकर चीनी मिलों में पेराई कि मध्य होने वाले पोस्ट- हारवेस्ट ह्रास से प्रति वर्ष लगभग 3000 से -5000 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा देश को उठाना पड़ रहा है।

यह बात शुक्रवार को भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के सभागार में गन्ना में पोस्ट हारवेस्ट प्रबन्धन विषय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में पूर्व महानिदेशक प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद डॉ.जीबी सिंह ने कही। प्रतिभागियों से कहा कि इस राजस्व घाटे को कम करने के लिए चीनी उद्योग को एक आदर्श कटाई व पेराई समय सारिणी बनाकर दृढ़ता के साथ काम करना होगा।

डॉ. सिंह ने अपने सम्बोधन में कहा कि गन्ना में सुकोज की मात्रा को और अधिक बढ़ाने के लिए आवश्यक शोध रणनीति पर विचार होना चाहिए तथा वैज्ञानिकों को इस दिशा में कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गन्ना की उत्पादकता बढ़ाकर चीनी उद्योग को एक नई दिशा मिल सकती है। चीनी उत्पादकता बढ़ाने से लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। अवसर पर अपनी बात रखते हुए पूर्व महानिदेशक ने कहा कि गन्ना अनुसंधान संस्थान की ओर से विकसित पोस्ट हारवेस्ट मैनेजमेन्ट माड्यूल को अपना कर उत्तर भारत में चीनी परता ह्रास को काफी हद तक कम किया जा सकता है। और चीनी उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है।

अमर उजाला
लखनऊ | शनिवार | 3 नवंबर 2012

# अन्य राज्यों के 30 गन्ना विशेषज्ञों को प्रशिक्षण

लखनऊ। उप्र. में सबसे ज्यादा क्षेत्र गन्ना बोया जाता है, लेकिन फसल तैयार होने के बाद ठीक प्रबंधन नहीं होने से हम उत्पादन में महाराष्ट्र और तमिलनाडु से पीछे हैं। यह जानकारी उप्र. कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक डॉ. जीबी सिंह ने शुक्रवार से भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित आठ दिवसीय प्रशिक्षण मॉड्यूल में दीं। इसमें पंजाब, उप्र, उत्तराखंड, बिहार और ओडिशा से 30 गन्ना विशेषज्ञों को प्रशिक्षण मिलेगा।